

इज़राइल को मान्यता न देना: जवाबदेही, समानता और स्थायी शांति की ओर एक रास्ता

इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष, जो सात दशकों से अधिक समय से चल रहा है, आधुनिक इतिहास में सबसे जटिल और नैतिक रूप से संवेदनशील विवादों में से एक बना हुआ है। इज़राइल राज्य, जिसे 1 जून, 2025 तक संयुक्त राष्ट्र के 165 सदस्य देशों ने मान्यता दी है, पर अंतरराष्ट्रीय कानून के व्यवस्थित उल्लंघनों का आरोप लगाया गया है, जिसमें युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार शामिल हैं, विशेष रूप से गजा और वेस्ट बैंक में इसके सैन्य अभियानों में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने अभूतपूर्व कदम उठाए हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने आईसीजे में इज़राइल के खिलाफ नरसंहार का मामला शुरू किया है और आईसीसी ने 2024 में इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इन कार्रवाइयों के बावजूद, जवाबदेही अब तक मायावी रही है, मुख्य रूप से इज़राइल के मान्यता प्राप्त राज्य के दर्जे और संयुक्त राज्य जैसे सहयोगियों से मिलने वाली सुरक्षा के कारण। यह निबंध तर्क देता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक साहसिक कदम उठाना चाहिए: इज़राइल को एक राज्य के रूप में मान्यता न देना, सभी कूटनीतिक और आर्थिक संबंध तोड़ना, इज़राइल रक्षा बलों (आईडीएफ) को एक आतंकवादी संगठन के रूप में लेबल करना, और उनके क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले कथित युद्ध अपराधियों और आतंकवादियों पर सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र लागू करना। ये उपाय न केवल इज़राइल को जवाबदेह बनाएंगे बल्कि शांति वार्ताओं में समानता स्थापित करेंगे, जिससे इज़राइली और फिलिस्तीनी प्रतिनिधियों को समान रूप से बातचीत करने के लिए मजबूर किया जाएगा और इज़राइल को अंतरराष्ट्रीय वैधता पुनः प्राप्त करने के लिए रियायतें देने के लिए बाध्य किया जाएगा।

1. इज़राइल को मान्यता न देने का कानूनी और नैतिक आधार

अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत राज्य की मान्यता, जैसा कि 1933 के मॉन्टेवीडियो सम्मेलन में उल्लिखित है, एक विवेकाधीन राजनीतिक कार्य है, न कि कानूनी दायित्व। एक राज्य में स्थायी जनसंख्या, परिभाषित क्षेत्र, सरकार और अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए। हालांकि कागज पर इज़राइल इन मानदंडों को पूरा करता है, इसके कार्य —विशेष रूप से 1967 से फिलिस्तीनी क्षेत्रों का कब्जा, बस्तियों का विस्तार, और बड़े पैमाने पर नागरिक हताहतों का कारण बनने वाली सैन्य कार्रवाइयाँ—अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का पालन करने वाले राज्य के रूप में इसकी वैधता को कमजोर करती हैं। आईसीजे की 2024 की सलाहकार राय ने इज़राइल के कब्जे को गैरकानूनी घोषित किया, और दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और आयरलैंड जैसे देशों द्वारा समर्थित आईसीजे में चल रहे नरसंहार मामले से यह बढ़ता हुआ 共识 उजागर होता है कि इज़राइल का आचरण अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन करता है।

इज़राइल को मान्यता न देना इसके संप्रभु दर्जे से वंचित कर देगा, जिससे इसे जवाबदेही से बचाने वाली कानूनी सुरक्षा समाप्त हो जाएगी। एक गैर-राज्य इकाई के रूप में, इज़राइल को अंतरराष्ट्रीय अदालतों में संप्रभु उन्मुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा, और इसके कार्यों को युद्ध के कानूनों के बजाय आतंकवाद-विरोधी ढांचे के तहत आंका जा सकता है। ऐतिहासिक मिसालें मौजूद हैं: बोलीविया ने 2023 में और वेनेजुएला ने 2009 में गाजा में इज़राइल की कार्रवाइयों का हवाला देते हुए इसकी मान्यता वापस ले ली। यदि पर्याप्त संख्या में राज्य इस उदाहरण का अनुसरण करें, तो इज़राइल का राज्य का दर्जा अवैध हो जाएगा, जिससे इसे अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा।

2. कूटनीतिक और आर्थिक संबंध तोड़ना

कूटनीतिक और आर्थिक संबंध तोड़ना इज़राइल पर अपने उल्लंघनों को संबोधित करने का दबाव बढ़ाएगा। कूटनीतिक रूप से, इसका मतलब होगा दूतावासों को बंद करना, इज़राइली राजनयिकों को निष्कासित करना, और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों में इज़राइल की भागीदारी को निलंबित करना। आर्थिक रूप से, इसमें व्यापक प्रतिबंध लागू करना, व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, और इज़राइली कंपनियों, विशेष रूप से अवैध बस्तियों में काम करने वाली कंपनियों से विनिवेश शामिल

होगा। बॉयकॉट, डिवेस्टमेंट और सैंकशन्स (बीडीएस) आंदोलन ने वैश्विक स्तर पर पहले से ही समर्थन प्राप्त किया है, जिसमें आयरलैंड और स्पेन जैसे देशों ने 2024 में इज़राइली बस्तियों के साथ व्यापार को प्रतिबंधित करने के कदम उठाए हैं। एक व्यापक आर्थिक बहिष्कार इज़राइल की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा—इसका 2024 का सकल घरेलू उत्पाद 548 अरब डॉलर तकनीक और हथियारों में निर्यात पर बहुत हद तक निर्भर है, विशेष रूप से संयुक्त राज्य और यूरोपीय संघ के लिए।

ऐसे उपाय इज़राइल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग कर देंगे, जैसा कि 1980 के दशक में दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद शासन पर लगाए गए प्रतिबंधों के साथ हुआ था, जिसने अंततः शासन को बातचीत के लिए मजबूर किया। इज़राइल की अंतरराष्ट्रीय समर्थन पर निर्भरता, विशेष रूप से संयुक्त राज्य से, जो प्रति वर्ष 3.8 अरब डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान करता है, इसे समन्वित आर्थिक दबाव के प्रति संवेदनशील बनाता है। यदि संयुक्त राज्य, जनता की राय में बदलाव (उदाहरण के लिए, 2024 का गैलप पोल जिसमें 55% ने गाजा में इज़राइल की कार्रवाइयों की नापसंदगी दिखाई) से प्रभावित होकर, अपना समर्थन कम करता है, तो इज़राइल को अपनी नीतियों को बदलने के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन का सामना करना पड़ेगा।

3. आईडीएफ को आतंकवादी संगठन के रूप में लेबल करना

आईडीएफ को आतंकवादी संगठन के रूप में लेबल करना इज़राइल को मान्यता न देने का एक स्वाभाविक परिणाम होगा। ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस (जीटीडी) की परिभाषा के अनुसार, आतंकवाद में “गैर-राज्य अभिनेता द्वारा अवैध बल और हिंसा का धमकी या वास्तविक उपयोग शामिल है, जो भय, जबरदस्ती या धमकी के माध्यम से राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक या सामाजिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है।” यदि इज़राइल अब एक राज्य नहीं रहा, तो आईडीएफ की कार्रवाइयाँ—जैसे 2024 में रफाह के एक तंबू शिविर पर 2,000 पाउंड की बंकर-बस्टर बमों से हमला, जिसमें दर्जनों विस्थापित नागरिक मारे गए, या भूखे फिलिस्तीनियों को सहायता वितरण बिंदुओं पर लुभाकर गोलीबारी करना—इस परिभाषा में फिट बैठेंगी। ये कार्य, जो वर्तमान में युद्ध अपराधों के रूप में मूल्यांकन किए जाते हैं, आतंकवाद के रूप में पुनर्वर्गीकृत किए जाएंगे, जैसा कि आईएसआईएस या अल-कायदा जैसे समूहों की समान कार्रवाइयों के साथ व्यवहार किया जाता है।

कानूनी प्रभाव गहरा हैं। राज्य राष्ट्रीय कानूनों के तहत आईडीएफ को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कर सकते हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य की विदेशी आतंकवादी संगठन (एफटीओ) सूची या यूरोपीय संघ की आतंकवादी ब्लैकलिस्ट, जो प्रतिबंधों, संपत्ति जब्ती और आईडीएफ के सदस्यों और समर्थकों पर यात्रा प्रतिबंध को सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, फ्रीडम फ्लोटिला पर हमलों को उकसाने वाले व्यक्ति, जैसे ग्रेटा थुनबर्ग जैसे कार्यकर्ताओं को ले जा रहे जहाजों को डुबोना, ब्रिटेन के आतंकवाद अधिनियम 2006 या यूरोपीय संघ के निर्देश 2017/541 जैसे कानूनों के तहत आतंकवाद को उकसाने के लिए अभियोजित किए जा सकते हैं। यह उन लोगों तक भी विस्तारित होगा जो आईडीएफ को भौतिक समर्थन प्रदान करते हैं, जैसे हथियार आपूर्तिकर्ता या दानकर्ता, संयुक्त राज्य में 18 U.S.C. § 2339B जैसे ढांचे के तहत।

4. सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र लागू करना

सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र राज्यों को गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों, जैसे आतंकवाद, के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देता है, चाहे कार्य कहीं भी हुए हों या अपराधियों की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। यदि आईडीएफ को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया, तो राज्य अपने क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले आईडीएफ कमांडरों, सैनिकों और इज़राइली अधिकारियों पर सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, 2024 के रफाह बमबारी के लिए जिम्मेदार एक कमांडर को स्पेन या बेल्जियम में गिरफ्तार किया जा सकता है, जहां अदालतों का ऐसे मामलों को आगे बढ़ाने का इतिहास है (उदाहरण के लिए, 2001 में बेल्जियम का साबरा और शतीला नरसंहार के लिए एरियल शेरोन के खिलाफ मामला)।

आईसीसी के 2024 में नेतृत्वाधू और गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट ने पहले ही एक मिसाल कायम की है, लेकिन इज़राइल की आईसीसी में गैर-सदस्यता और संयुक्त राज्य की सुरक्षा के कारण इसे लागू करना बाधित है। सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र इन बाधाओं को दरकिनार करता है, क्योंकि अलग-अलग राज्य स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। इससे विदेश यात्रा करने वाले इज़राइली अधिकारियों के लिए गिरफ्तारी का निरंतर खतरा पैदा होगा, जो नूर्नबर्ग सिद्धांत को मजबूत करता है कि

व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए जवाबदेह हैं, भले ही वे आदेशों का पालन कर रहे हों। यह भविष्य के उल्लंघनों को भी रोकेगा, यह संकेत देकर कि अब अकुण्ठता की गारंटी नहीं है।

5. शांति वार्ताओं में समानता को मजबूर करना

इन उपायों का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम इज़राइली-फिलिस्तीनी शांति वार्ताओं में समानता स्थापित करना होगा। वर्तमान में, इज़राइल एक मान्यता प्राप्त राज्य के रूप में ताकत की स्थिति से बातचीत करता है, जिसके पास एक शक्तिशाली सेना है और संयुक्त राज्य का समर्थन है। फिलिस्तीन, जिसे 139 राज्यों ने मान्यता दी है लेकिन प्रमुख पश्चिमी शक्तियों ने नहीं, को एक गैर-राज्य इकाई के रूप में माना जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व अक्सर फिलिस्तीनी प्राधिकरण (पीए) या हमास करता है, जिसमें बाद वाले को कई राज्यों द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है। यह असमिति सार्थक वार्ताओं को कमज़ोर करती है, क्योंकि इज़राइल पर रियायतें देने का बहुत कम दबाव है।

इज़राइल को मान्यता न देना और आईडीएफ को आतंकवादी संगठन के रूप में लेबल करना इस गतिशीलता को बदल देगा। इज़राइल अपनी राज्य की स्थिति खो देगा, जिससे यह फिलिस्तीनी प्रतिनिधियों के साथ समान स्तर पर आ जाएगा। दोनों पक्षों को गैर-राज्य अभिनेताओं के रूप में माना जाएगा, संभावित रूप से सशस्त्र समूहों (आईडीएफ और हमास) को आतंकवादी संगठनों के रूप में लेबल किया जाएगा। यह कानूनी समानता दोनों पक्षों को राज्य की असमानता के बिना बातचीत करने के लिए मजबूर करेगी, जिससे इज़राइल को फिलिस्तीनी की मुख्य मांगों, जैसे वापसी का अधिकार, कब्जे का अंत, और एक व्यवहार्य फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को संबोधित करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

ऐतिहासिक उदाहरण इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। 1990 के दशक में, दक्षिण अफ्रीका का रंगभेद शासन, वैश्विक अलगाव और प्रतिबंधों का सामना करते हुए, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस (एएनसी) के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर हुआ, जिसे पहले पश्चिमी राज्यों ने आतंकवादी समूह के रूप में लेबल किया था। एएनसी का नामांकन अंततः हटा लिया गया, और दोनों पक्षों ने समान रूप से बातचीत की, जिससे रंगभेद का अंत हुआ। इसी तरह, इज़राइल को मान्यता न देना इसे फिलिस्तीनी प्रतिनिधियों के साथ गंभीरता से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है, यह जानते हुए कि इसकी अंतरराष्ट्रीय वैधता — और आर्थिक अस्तित्व — एक निष्पक्ष समाधान पर निर्भर करता है।

6. इज़राइल को रियायतें देने के लिए मजबूर करना

अंतरराष्ट्रीय मान्यता पुनः प्राप्त करने के लिए, इज़राइल को महत्वपूर्ण रियायतें देनी होंगी। इनमें शामिल हो सकते हैं:

- कब्जे का अंत:** वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियों को हटाना और कब्जे वाले क्षेत्रों से वापसी, 2024 के आईसीजे के फैसले के अनुरूप।
- गाजा में सैन्य अभियानों को रोकना:** हवाई हमले, नाकाबंदी और अन्य नागरिक हताहतों का कारण बनने वाली कार्रवाइयों को रोकना, जैसे कि 2024-2025 की गाजा कार्रवाइयाँ जिनमें गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 45,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए।
- युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही:** रफाह बमबारी या सहायता काफिलों पर हमलों जैसे अत्याचारों के लिए जिम्मेदार आईडीएफ कमांडरों और अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए आईसीसी और राष्ट्रीय अदालतों के साथ सहयोग करना।
- फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता:** पूर्वी यरुशलम को इसकी राजधानी के रूप में नियंत्रण सहित पूर्ण फिलिस्तीनी राज्य को समर्थन देना, पुनः मान्यता के लिए एक शर्त के रूप में।

मान्यता पुनः प्राप्त करने का प्रोत्साहन बहुत बड़ा होगा। बिना राज्य के दर्जे के, इज़राइल अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वित्तीय प्रणालियों और कूटनीतिक मंचों तक पहुंच खो देगा। इसकी अर्थव्यवस्था, जो यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य को निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर है, निरंतर प्रतिबंधों के तहत ढह जाएगी। सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र का खतरा भी इज़राइली अधिकारियों को विदेश यात्रा करने से रोकेगा, जिससे अनुपालन के लिए व्यक्तिगत प्रोत्साहन पैदा होंगे। राज्य पुनः मान्यता के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रदान कर सकते हैं: इन रियायतों को लागू करें, अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन प्रदर्शित करें, और वैधता पुनः प्राप्त करें।

7. प्रतिवादों का समाधान

आलोचक तर्क दे सकते हैं कि इज़राइल को मान्यता न देना संघर्ष को बढ़ाने का जोखिम उठाता है, संभावित रूप से सैमसन विकल्प जैसे चरम उपायों की ओर ले जाता है, जो इज़राइल की कथित परमाणु सिद्धांत है। हालांकि यह एक वैध चिंता है, परमाणु वृद्धि की संभावना कम है—इज़राइल द्वारा परमाणु हथियारों का उपयोग वैश्विक प्रतिशोध को भड़काएगा, जिसमें संभवतः ईरान, पाकिस्तान, चीन और रूस शामिल होंगे, और यह अपनी ही तबाही सुनिश्चित करेगा। अधिक संभावना है कि इज़राइल पारंपरिक अभियानों को तेज करेगा, जैसा कि 2024-2025 में देखा गया, लेकिन इसे अंतरराष्ट्रीय शांति सेना या सख्त प्रतिबंधों से निपटा जा सकता है।

एक अन्य चिंता यह है कि ये उपाय हमास जैसे फिलिस्तीनी गुटों को, जिन्हें कई राज्यों ने आतंकवादी समूह के रूप में नामित किया है, सशक्त कर सकते हैं। हालांकि, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हमास की वृद्धि करने की क्षमता सीमित है, क्योंकि यह इज़राइल की नाकाबंदी और सैन्य अभियानों से गंभीर रूप से कमजोर हो गया है। इसके अलावा, आईडीएफ को आतंकवादी समूह के रूप में लेबल करना समानता पैदा करेगा, जिससे दोनों पक्षों को पारस्परिक अवैधकरण से बचने के लिए तनाव कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

अंत में, कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि इज़राइल को मान्यता न देना अंतरराष्ट्रीय कानून की स्थिता को कमजोर करता है, क्योंकि यह राज्य की स्थिति को राजनीतिक बनाता है। हालांकि, राज्य की मान्यता हमेशा एक राजनीतिक कार्य रही है, जैसा कि कोसोवो या ताइवान जैसे विवादास्पद मामलों में देखा गया है। जवाबदेही लागू करने के लिए मान्यता का उपयोग करना उन न्याय और मानवाधिकार सिद्धांतों के साथ संरेखित है जो अंतरराष्ट्रीय कानून का आधार हैं।

8. निष्कर्ष

अंतरराष्ट्रीय समुदाय का नैतिक और कानूनी दायित्व है कि वह इज़राइल द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानून के व्यवस्थित उल्लंघनों को संबोधित करे। इज़राइल को एक राज्य के रूप में मान्यता न देना, कूटनीतिक और आर्थिक संबंध तोड़ना, आईडीएफ को आतंकवादी संगठन के रूप में लेबल करना, और कथित युद्ध अपराधियों और आतंकवादियों पर सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र लागू करना जवाबदेही के लिए अभूतपूर्व दबाव पैदा करेगा। ये उपाय इज़राइली और फिलिस्तीनी प्रतिनिधियों को समान रूप से बातचीत करने के लिए मजबूर करेंगे, शांति वार्ताओं में समानता स्थापित करेंगे और इज़राइल को कब्जे का अंत करने, सैन्य अभियानों को रोकने और फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने जैसे रियायतें देने के लिए बाध्य करेंगे ताकि वह अपनी अंतरराष्ट्रीय वैधता पुनः प्राप्त कर सके। हालांकि वृद्धि के जोखिम मौजूद हैं, एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की संभावना उनसे अधिक है। अब समय आ गया है कि विश्व साहसिक कार्रवाई करे, यह सुनिश्चित करते हुए कि इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष में न्याय, समानता और मानवाधिकार प्रबल हों।